

नई दिल्ली में बिना बिजली की सरकारी इमारतें

*522. श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में ऐसी इमारतों में, जिनमें बिजली नहीं लगाई गई है, रहने वाले लोग किस किस श्रेणी के हैं ; और

(ख) इन इमारतों में बिजली नहीं लगाने के कारण क्या हैं ?

t [GOVERNMENT BUILDINGS IN NEW DELHI WITHOUT ELECTRICITY

*833. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state:

(a) the categories of the persons who occupy the Government buildings in New Delhi which are not provided with electricity; and

(b) the reasons for not supplying electricity to these buildings?]

कार्य, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख), केवल चौथे दरजे और वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों के क्वार्टरों में ही बिजली लगाना बाकी है। इन क्वार्टरों में भी बिजली लगाने का काम हो रहा है।

t[THE MINISTER FOR WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SARDAR SWARAN SINGH) : (a) and (b). Only the quarters of Class IV and work-charged staff remained unelectrified. The electrification of even these quarters is now in progress.]

श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या इन इमारतों में रहने वाले लोगों ने बिजली लगाने की दरखास्त दी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उनके दरखास्त देने या न देने से बिजली लगाने का फैसला नहीं होता। सरकार ने खुद फैसला कर दिया है कि इन

क्वार्टरों में बिजली लगानी, खाह वे दरखास्त दें या नहीं।

श्री कृष्णकान्त व्यास : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन लोगों की दरखास्तें प्राप्त हुई हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अलग अलग से दरखास्त देने से किसी क्वार्टर में बिजली नहीं लगती जबकि सरकार सभी सरकारी क्वार्टरों में बिजली लगाने वाली है।

दियासलाई के छोट पमाने के उद्योगों द्वारा उत्पादन

*528. श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५४ के अन्त तक देश में दियासलाई के कितने छोट पमाने के उद्योग काम कर रहे थे ;

(ख) दियासलाई के इन छोट पमाने के उद्योगों की उत्पादन सामर्थ्य क्या है और देश के समस्त उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग इन उद्योगों द्वारा बनाया जाता है ; और

(ग) दियासलाई के छोट पमाने के उद्योगों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या उपाय अपनाए हैं ?

11 PRODUCTION BY SMALL-SCALE MATCH FACTORIES

*834. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many small-scale match factories were working in the country by the end of the year 1954;

(b) what is the capacity of production of these small-scale match factories and what percentage of the total production of the country is produced by these factories; and

(c) what are the means adopted by Government to protect the small-scale match factories?]

श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या यह सच है कि बड़े कारखानों का इस उद्योग पर बड़े पैमाने पर आधिपत्य होने के कारण वे बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं ? यदि हां, तो कुटीर उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कोई उपकरण लगाने का विचार रखती है ?

(ख) छोटें पैमाने के कारखानों की उत्पादन क्षमता का अन्दाज लगाना कठिन है । परन्तु यह कारखाने भारत में होने वाले दियासलाई उत्पादन का लगभग ३५ प्र० श० भाग तैयार करते हैं ।

(ग) छोटें पैमाने के कारखानों पर उत्पादन शुल्क की प्राथमिकता पूर्ण दर लागू होती है ।

[THE DEPUTY MINISTER FOR COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI N. KANTJINGO) : (a) Reported to be about 180.

(b) Production capacity of small scale units is difficult to assess. These units, however, produce about 35 per cent, of the total match production in India.

(c) Small-scale units enjoy preferential rates of excise duty.]

श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या छोटें दियासलाई निर्माताओं ने बड़े बड़े कारखानों से संरक्षण दिये जाने की मांग की है ?

श्री एन० कानूनगो : हां, इसीलिए अलग अलग रेट की एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है ।

श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या सरकार की यह नीति है कि छोटें छोटें निर्माताओं की सहायता की जाय और यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री एन० कानूनगो : यह तो सरकार की पालिसी है और इसी कारण छोटें कारखानों के लिए एक्साइज ड्यूटी के रेट कम कर दिये गये हैं और उनकी मार्केटिंग की स्कीम को चलाने

का प्रबन्ध खादी इंडस्ट्री बोर्ड कर रही है । इस काम के लिए १९,५०० रुपये ग्रांट और एक लाख ९० हजार रुपये लॉन्स के रूप में दिया गया है । और इससे भी ज्यादा देने का विचार है ।

श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या यह सच है कि बड़े कारखानों का इस उद्योग पर बड़े पैमाने पर आधिपत्य होने के कारण वे बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं ? यदि हां, तो कुटीर उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कोई उपकरण लगाने का विचार रखती है ?

श्री एन० कानूनगो : इसीलिए तो सरकार ने बड़े बड़े कारखानों पर एक्साइज ड्यूटी लगाई है । जहां तक पहले सवाल का पहला हिस्सा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या यह सच है कि इस उद्योग में जितने बड़े कारखाने हैं उनमें अधिकांश पूंजी विदेशियों की लगी हुई है ?

श्री एन० कानूनगो : हां, ज्यादातर विदेशी पूंजी लगी हुई है ।

श्री कृष्णकान्त व्यास : भारत में दियासलाई का कितना कच्चा माल उपलब्ध है ?

MR. CHAIRMAN: That will do.

SHRI S. MAHANTY: Is it a fact that about 90 per cent, of the total match production is concentrated in one foreign concern, Wimco?

SHRI N. KANUNGO: It is not 90 per cent.; it is near about 60 per cent.

SHRI S. MAHANTY: May I know how these small-scale match factories will get protection in view of the fact that this one unit produces more than 60 per cent?

SHRI N. KANUNGO: Because efforts have not been made earlier to give incentive to small producers, but incentives are now being given and with the operation of marketing I schemes and with preferential rates of excise duty, the small scale units-

will be able to stand on their own legs.

SHRI S. MAHANTY: In view of the fact that small units cannot compete with Wimco both in production and in price what steps do Government propose to restrict the production of Wimco for giving protection to the small-scale factories?

SHRI N. KANUNGO: I do not agree with the inference contained in the first part of the question. The small-scale units, with proper organisation and marketing facilities, can compete.

SHRI T. V. KAMALASWAMY: Has any small-scale match factory been closed down in the past two years?

SHRI N. KANUNGO: Some have closed down in the past but not in recent months.

DR. SHRIMATI SEETA PARMA-NAND: In that case why did the Government curtail the production of cotton textiles in order to give protection and incentive to *khadi* industry?

MR. CHAIRMAN: That is another question.

DR. SHRIMATI SEETA PARMA-NAND: Same principle, Sir.

MR. CHAIRMAN: The principle is the same in all cases.

श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या भारत में दियास-लाई बनाने का सारा कच्चा माल उपलब्ध है ?

श्री एन० कानूनगो : सारा कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, कुछ कौमिकल बाहर से मंगाना पड़ता है ।

SHRI S. MAHANTY: How many small-scale factories are still left to be closed down?

(2Vo reply)

आमला और बहेड़ा का निर्यात

***535. श्री कृष्णकान्त व्यास :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पक्का रंग बनाने के काम में आने वाले आमलों और बहेड़ों की कितनी मात्रा किन किन देशों को निर्यात की जाती है ;

(ख) सन् १९५०, १९५१, १९५२, १९५३ तथा १९५४ में निर्यात किये गए आमले और बहेड़ों की कुल मात्रा तथा मूल्य क्या है ; और

(ग) भारत में किन किन उद्योगों तथा कारखानों में आमला और बहेड़ा काम में लाया जाता है ?

t [EXPORT OF "AMLA" AND "BAHEKA"]

*835. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) what quantities of, and the countries to which, *amla* and *bahera* used for manufacturing fast colours are exported;

(b) the total quantity and value of *amla* and *bahera* exported in the years 1950, 1951, 1952, 1953 and 1954; and

(c) the names of the industries and the factories in India where *amla* and *bahera* are consumed?]

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री एन० कानूनगो) : (क) और (ख). समुद्र द्वारा होने वाले व्यापार के लेखों में आमला और बहेड़ों के निर्यात का अलग उल्लेख नहीं किया जाता ।

(ग) ठीक ठीक और पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

f[THE DEPUTY MINISTER FOR COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI N. KANUNGO): (a) and (b). Exports of *amla* and *bahera* are not recorded separately in Sea-borne Trade Accounts.

(c) Precise and complete information is not available.]

*836. [For answer, vide col. 6346 infra.]